क्षेत्र में कई लोग ये कारखाने लगाने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोगों ने प्रारंभ भी किए हैं। जब केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ये कारखाने लगाने में असमर्थ है; तो क्या वह आर्थिक सहयोग और अनुदान दे कर हर राज्य में पशु आहार के उत्पादन को प्रोत्साहन देगी, ताकि पशु आहार अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सके, जिससे अच्छे पशुओं की संख्या और दूध की मात्रा में वृद्धि हो सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना: पशुओं की नस्ल को सुधारने और मिल्क की पैदावार को बढ़ाने के काम को गवर्नमेंट आपेरेशन फ्लड और कई अन्य प्रोग्राम्स के माध्यम से कर रही है। कोआपरेटिव सैक्टर में भी यह काम आगे बढ़ रहा है। उसमें हर स्टेट में एक कैटल फण्ड का प्लांट लगाने का विचार है। इस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया की मंशा ऐसा प्लांट लगाने की नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पशुओं के आहार के उत्पादन के लिए जो कारखाने चल रहे हैं, उनके बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या लाभ कमाना उन कारखानों की सफलता की कसौटी है या यह देखा जाता है कि वे किस मात्रा तक मांग को पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कारखाने नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चल रहे हैं। इस कसौटी को अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? महाराष्ट्र के कारखाने ने 80.50 लाख रुपया कमाया है। क्या इन कारखानों का उद्देश्य रुपया कमाना है या किसान के लिए उपयोगी चारा उपलब्ध करना है?

श्री योगेन्द्र मकवाना: लास तो कोई कारखाना नहीं कर सकता। खास तौर से जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, उनके द्वारा ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जाता है, जिससे किसानों को बहुत नुक्सान हो। लेकिन कारखाने को चलाने के लिए, और उसको घाटा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्राइस फिक्स की जाती है। लेकिन अभी तो ज्यादा कोआपरेटिव सोसायटीज के अन्तर्गत ही हैं और जिनमें से एक कोआपरेटिव सोसायटी खुद फार्मर्स की है और इस प्रकार जो भी मुनाफा आता है वह फार्मर्स के पास ही जाता है। अतः इसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है।

Breakthrough in Intensive fish farming

*869. SHRI B. V. DESAI† :
SHRI P. M. SAYEED :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Inland fishery scientists have achieved a major breakthrough in intensive farming technology ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent to which it will be helpful in fish farming and the steps taken to utilise the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

(b) The inland fisheries scientists have achieved a major breakthrough in intensive fish farming relevant to drainable and non-drainable ponds ; prawn and fish culture in low lying paddy fields ; integrated fish farming systems ; pen culture in bheels ; cage culture in tanks ; air breathing fish culture for magur, singhi and murrels and fisheries development in ox-bow lakes andj reservoirs.

A production rate of 3-11 tonnes/ha/yr in composite fish culture at the Central Inland Fisheries Research Institute's own farms as well as in State owned farms under different agro-climatic conditions has been achieved. Fish production at rates of 4 tonnes/ha/yr in large water bodies (2 ha and above) ; 6 to 7 tonnes/ha/yr in pig-cum-fish culture ; 3.5 to 4 tonnes/ha/yr in duck-cum-fish culture ; 5.5 tonnes of paddy and 700 kg. of fish/ha/10 months in paddy-cum-fish culture ; 4 tonnes of fish/ha/6 months in pen culture with potential for two crops in a year ; in cage culture/160 kg/10.5 m^2/6 months (=over 1

tonne of fish in 50 sq. m/yr) ; 500 kg./ha/8 months of giant prawn in treated sewage-fed fish ponds ; about 1 tonne/ha/yr in managed ox-bow lakes ; 50 to 80 kg. fish/ha/yr in well managed large reservoirs ; 7.8 tonnes/ha/5 months for magur ; 7 tonnes/ha/5 months for singhi have been acheived. In addition, the Institute has made a breakthrough in breeding Indian and exotic carps during off season and breeding of Indian carps in upland waters. Success has also been achieved in mahasser breeding and seed production.

(c) Carp polyculture technology developed by the Central Inland Fisheries Research Institute can be adopted in an estimated 1.6 million hectare water area for small and large ponds and tanks in sizes ranging upto 20 hectares and an average yield of 3 tonnes/ha can be easily achieved at farmers level.

Many of the technologies developed by the Institute are presently implemented by the States through FFDAs, IRDP, TRYSEM etc. Government of India has also developed carp hatcheries and augmented areas under fish seed farms for enhanced production of quality seed to meet the emerging demands of intensive fish culture through World assisted inland fisheries project and under Centrally sponsored schemes.

129 Fish Farmers' Development Agencies have been established to transfer intensive fish farming technology developed by inland fishery scientists to fish farmers. These agencies so far have brought 52,641 ha under fish farming giving an average production of 681 kg/ha. These agencies have trained 42,475 fish farmers in intensive fish farming.

श्री बी० वी० देसाई: अध्यक्ष महोदय, मैं शाकाहारी हूं इसलिए मछली के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। यदि पी एम सईद साहब यहां पर उपस्थित रहे होते तो अधिक अच्छा होता ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से शाकाहारी भी मछली खाते हैं ।

श्री बी० वी० देसाई : मछली को जल तरोई भी कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से जो छोटे फार्मर्स हैं जो लीज पर पाण्ड्स लेकर फिश फार्मिंग करते हैं वे जब बैंकों के पास या दूसरी जगह लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती है। पांच हजार तक के लोन के लिए सिक्योरिटी की मांग नहीं होनी चाहिये। इस सिलसिले में क्या माननीय मन्त्री जी जानकारी देंगे कि जो ऐसे फार्मर्स हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है सिक्योरिटी देने की और जो पाण्ड्स लीज पर लेकर फिशिंग करना चाहेंगे, उनको बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जायेगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : फिश फार्मर्स डेवलपमेन्ट एजेंसीज जहां जहां पर हैं वहां बैंकों से लोन दिलवाने का प्राविजन है और फिशरमेन को लोन दिलवाते भी हैं ।

मछुओं के कल्याण के लिए विदेशी सहायता

*871. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को मछुओं की दशा सुधारने और मछली उत्पादन के विकास के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) सरकार ने इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया है और तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मात्स्यकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त बहुपक्षीय सहायता की राशि और इसके उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--